शुक्रवार , 30 अक्टूबर 2026, ठाणे, मुंबई

दैनिक
सिटी न्यूज
मुंबई

सच का जोश

वर्ष - 15 • अंक - 46 CITY NEWS MUMBAI

पुलिस की लाठियों की चिंता मत करो

राहुल गांधी की जनता से अपील, कहा- 1 नवंबर को दिल्ली चलो मार्च में शामिल हो

राहुल गांधी ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाले दिल्ली मार्च में शामिल होने की अपील की। यह प्रदर्शन वोट चोरी, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के मुद्दों पर केंद्रित है। रा लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश की जनता से 1 नवंबर को केंद्र सरकार के खिलाफ आयोजित होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 'चलो दिल्ली' रामलीला मार्च, लोकतंत्र को बचाने का, वोट चोरी को रोकने का, संविधान को बचाने का मार्च है। यह किसी एक राजनीतिक पार्टी का मार्च नहीं - यह भारत की आत्मा का मार्च है। राहुल गांधी ने कहा वे सब लोग जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार से परेशान हैं। सब लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आप सब आइए। एक ही प्रोटेस्ट है - देश का प्रोटेस्ट है। पुलिस की लाठियों की चिंता मत करोः राहुल गांधी राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश पोस्ट करते हुए कहा पुलिस की चिंता मत



करो, लाठियों की चिंता मत करो। बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं होगी वो आप पर कोई कार्रवाई कर सके। उन्होंने कहा, आइए हमारे साथ मार्च करिए। हम संविधान की रक्षा के लिए, भारतीय राष्ट्र की रक्षा के लिए साथ चलेंगे। हुल गांधी ने 1 नवंबर को दिल्ली मार्च में शामिल होने की अपील की कांग्रेस ने प्रदर्शन को वोट चोरी और संविधान की रक्षा से जोड़ा इंडिया गठबंधन 30 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई करेगा कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि मैं सभी छात्रों समूहों से अपील करता हूं, चाहे आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों, अगर आपको लगता है कि भारत पर हमला हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आप पर हमला हो रहा है, आपकी बात, आपके विचार, आपके सोचने के तरीके पर हमला हो रहा है, तो आइए और हमारे साथ जुड़िए। राहुल ने कहा, यह एक शानदार मार्च होगा, यह इस देश की आत्मा के लिए एक मार्च है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का जन महाभियोग इंडिया गठबंधन 30 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के 10, राजाजी मार्ग वाले घर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'जन महाभियोग' की कार्रवाई करेगा, यह कार्रवाई वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर की जाएगी।

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट और CJI से मांगी बिना शर्त माफी, 17 नवंबर को पेशी का आदेश

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने न्यायपालिका पर विवादित टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। अदालत ने उन्हें 17 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया। संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश से बिना शर्त माफी मांगी। हलफनामे में भविष्य में न्यायपालिका पर बयान देते समय सावधानी बरतने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने राउत को 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने न्यायपालिका के खिलाफ अपनी टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से बिना शर्त माफी मांगी है। अवमानना



नोटिस के बाद राउत ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर अपने बयानों पर खेद जताया। हालांकि, माफीनामा अदालत के रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं होने और सुनवाई के दौरान उनकी ओर से वकील के पेश नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हलफनामे में क्या कहा? संजय राउत ने अपने हलफनामे में कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट की गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकार को बनाए रखने के महत्व को समझते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका अदालत के प्रति अनादर दिखाने या न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और अधिकार को कम करने का कोई इरादा नहीं था। राउत ने अपने बयानों के लिए बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि कुछ टिप्पणियां पर्याप्त सावधानी बरते बिना और पुष्टि किए बिना की गई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य अदालत की छवि खराब करना, किसी न्यायाधीश की स्वतंत्रता या निष्पक्षता पर सवाल उठाना अथवा न्याय प्रशासन में बाधा डालना नहीं था। भविष्य में सावधानी बरतने का आश्वासन हलफनामे में संजय राउत ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में ...शेष 7 पर

शिवसेना विवादः सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की दलील, विधायकों के बहुमत के आधार पर तय हो पार्टी का नेतृत्व



सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना नाम-निशान विवाद पर सुनवाई के दौरान शिंदे गुट ने पार्टी के आंतरिक चुनाव न होने और विधायकों के बहुमत को फैसला करने का मुख्य आधार बताया। शिवसेना नाम और चुनाव चिह्न विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। शिंदे गुट ने विधायकों के बहुमत और पार्टी के आंतरिक चुनावों का मुद्दा उठाया। चुनाव आयोग के अधिकार और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर भी दलीलें पेश की गईं। शिवसेना पार्टी के नाम व चिह्न पर कब्जे को लेकर उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे गुट के बीच सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जारी है। बुधवार को इस मामले पर एक बार फिर शुरू हुई सुनवाई में शिंदे गुट की ओर से सीनियर वकील ...शेष 7 पर

जापानी निवेश का प्रमुख केंद्र बन रहा महाराष्ट्र, मुंबई में JCCI प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक



मुंबई में JCCI के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक। महाराष्ट्र में जापानी निवेश, ऑटोमोबाइल और एयरोस्पेस समेत कई क्षेत्रों में व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। मुंबई में जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक में महाराष्ट्र में निवेश बढ़ाने पर चर्चा हुई। ऑटोमोबाइल और एयरोस्पेस समेत कई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापारिक सहयोग को दिशा मिलेगी। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण महाराष्ट्र निवेशकों के लिए अत्यधिक आकर्षक बन रहा है।

MPSC परीक्षा धांधली मामले में बड़ी कार्रवाई, तुकाराम मुंढे ने की अपील, 16 नवंबर तक मांगे हलफनामे और दस्तावेज

MPSC परीक्षा धांधली मामलों की जांच तेज, जांच आयोग के सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे ने अभ्यर्थियों और नागरिकों से 16 नवंबर तक हलफनामे और दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपील की। MPSC परीक्षा धांधली की जांच के लिए नया आयोग गठित हुआ है। तुकाराम मुंढे ने अभ्यर्थियों से सोलह नवंबर तक हलफनामे मांगे हैं। परीक्षार्थियों को अपने दस्तावेज और शिकायतें तय समय में भेजनी होंगी। MPSC द्वारा आयोजित विविध स्पर्धा परीक्षाओं में प्रश्नपत्रिका या उत्तरतालिका लीक होने के कथित मामलों की



जांच के लिए गठित जांच आयोग ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस जांच आयोग के सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी तुकाराम मुंढे ने अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों, आम नागरिकों और संबंधित पंजीकृत संस्थाओं से एक महत्वपूर्ण अपील जारी की है। उन्होंने आग्रह किया है कि इस प्रकरण से जुड़ी जानकारी, शिकायतें, निवेदन और प्रासंगिक साक्ष्य दस्तावेज 16 नवंबर 2026 तक हलफनामे के साथ आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग MPSC की विभिन्न परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं और गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग के प्रशासनिक संचालन और प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से लागू करने के लिए तुकाराम मुंढे को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जांच के दायरे में आई MPSC की ये ...शेष 7 पर

एथेनॉल से चलेंगी गाड़ियां, लेकिन इतनी सप्लाई आएगी कहां से? सुप्रीम कोर्ट का सरकार से सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने 100% एथेनॉल से चलने वाले वाहनों के लिए ईंधन की पर्याप्त सप्लाई पर केंद्र से सवाल किया। अदालत ने एथेनॉल नीति में किसानों के हित और पर्यावरण को भी अहम बताया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 100% एथेनॉल वाहनों के लिए पर्याप्त ईंधन की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित होगी। अदालत ने एथेनॉल नीति में किसानों के सशक्तीकरण और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। E100 वाहनों के उत्सर्जन प्रमाणन नियमों में बदलाव हुआ है, लेकिन पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की सीमा बढ़ाने की तत्काल योजना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा कि अगर 100 फीसदी एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को अनुमति दी जाती है, तो उनकी ईंधन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त एथेनॉल की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाएगी। अदालत ने कहा कि एथेनॉल नीति पर विचार करते समय व्यापक जनहित, पर्यावरण संरक्षण और किसानों के सशक्तीकरण को भी ध्यान में रखना जरूरी है। जस्टिस एमएम सुंदरश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ एथेनॉल सप्लाई वर्ष 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान पीठ ने हाल की मीडिया रिपोर्टों का उल्लेख किया, जिनमें 100 फीसदी एथेनॉल से



चलने वाले वाहनों को अनुमति दिए जाने की बात कही गई थी। पीठ ने सवाल किया कि अगर ऐसे वाहनों को अनुमति मिलती है, तो उनकी मांग के अनुरूप ईंधन की आपूर्ति कैसे की जाएगी। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कहा कि इसके लिए बड़े पैमाने पर विनिर्माण व्यवस्था में बदलाव करने होंगे। किसानों को सशक्त बनाने पर भी जोर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एथेनॉल से जुड़े फैसलों को केवल ईंधन की उपलब्धता तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसके व्यापक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर भी विचार होना चाहिए। जस्टिस सुंदरश ने किसानों के हितों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि देश की बड़ी आबादी गांवों में रहती है और किसानों को सशक्त बनाने के पहलू पर पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि किसानों के सशक्तीकरण को भी इस मुद्दे का अहम हिस्सा बनाया जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह अपनी दलीलों में किसानों से जुड़े पहलुओं पर भी बात करेंगे। एथेनॉल से किसानों को फायदा होने की दलील सुनवाई के दौरान एक वकील ने दलील दी कि एथेनॉल को बढ़ावा देने से किसानों को किसी न किसी रूप में लाभ हो सकता है। वहीं, दूसरे वकील ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति में किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई नवंबर में तय की है। E100 वाहनों को लेकर क्या है नया नियम? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अक्टूबर को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन अधिसूचित किया था। इसके तहत E100 तक एथेनॉल मिश्रण पर चलने में सक्षम फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए उत्सर्जन प्रमाणन संबंधी प्रावधानों में बदलाव किया गया है।

बिहार म्यूजियम ने पेरिस के लूव्र और न्यूयॉर्क के द मेट को पछाड़ा, विश्व के टॉप 10 लिस्ट में शामिल

वर्थ अ जर्नी की वर्ल्ड्स 100 बेस्ट म्यूजियम्स 2026 सूची में बिहार संग्रहालय को विश्व स्तर पर नौवां और एशिया में पहला स्थान मिला है। बिहार म्यूजियम ने विश्व के टॉप 10 की सूची में जगह बनाई पेरिस के लूव्र और न्यूयॉर्क के द मेट को पीछे छोड़ा पटना के बेली रोड में स्थित है बिहार म्यूजियम पटना स्थित बिहार म्यूजियम को 2026 में दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों की सूची में नौवां स्थान मिला है। यात्रा मार्गदर्शिका 'वर्थ अ जर्नी' द्वारा प्रकाशित इस सूची में भारत का यह एकमात्र संग्रहालय है। शीर्ष पांच संग्रहालयों में मेक्सिको सिटी का म्यूजियो नैशनल डी एंथ्रोपोलोजिया, मैड्रिड का म्यूजियो डेल प्राडो, डेनमार्क के हुमलेबेक स्थित लुइसियाना म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, सेंट पीटर्सबर्ग का स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम और वियना का कुन्स्टहिस्टोरिस्चेस म्यूजियम शामिल हैं। बिहार संग्रहालय ने शीर्ष पांच में जगह बनाने के लिए



पेरिस के लौवर और न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट को पीछे छोड़ दिया। यह शीर्ष 10 में शामिल होने वाला एकमात्र एशियाई संग्रहालय भी है। साल 2015 में उद्घाटन हुआ था पटना के बेली रोड पर स्थित इस संग्रहालय में ऐतिहासिक कलाकृतियों, मूर्तियों, सिक्कों, पांडुलिपियों और लोक कला का उल्लेखनीय संग्रह है। पटना म्यूजियम का उद्घाटन 2015 में हुआ था। इसका निर्माण वास्तव में इसलिए किया गया था ताकि पुराने पटना संग्रहालय में रखी कलाकृतियों को ठीक से प्रदर्शित किया जा सके। प्रित्जकर पुरस्कार विजेता जापानी वास्तुकार फुमिहिको माक ने मुंबई स्थित ओपोलिस आर्किटेक्ट्स के सहयोग से इस संरचना का डिजाइन तैयार किया। संस्कृति और विज्ञान से जुड़ी प्रदर्शनियां संग्रहालय में प्राचीन भारत से लेकर 1764 तक की कलाकृतियाँ प्रदर्शित हैं। दीर्घाओं को मौर्य काल से लेकर मुगल और सूर वंश तक के विभिन्न ऐतिहासिक काल के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। यहां एक बाल दीर्घा भी है, जिसमें पशु, लोक कला, संस्कृति और विज्ञान से संबंधित प्रदर्शनियां हैं। संग्रहालय की प्रवासी दीर्घा बिहार की भौगोलिक सीमाओं से परे उपस्थिति को दर्शाती है। संग्रह की प्रमुख कृतियों में से एक मौर्य काल की दीदारगंज यक्षी है, जो प्राचीन भारतीय मूर्तिकला की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। यह 1917 में पटना के पास पाई गई थी। सुबहर 10 बजे से शाम 5 बजे तक कर सकते हैं भ्रमण संग्रहालय में कुषाण काल की 'बुद्ध का जन्म' नामक मूर्ति वाली एक आयताकार शिला भी रखी है। इसके अलावा, पाल वंश की कुरकिहार बुद्ध की कांस्य प्रतिमा, कुरान की एक सचित्र पांडुलिपि और सूर वंश के सिक्के भी प्रदर्शित हैं। मुख्य गैलरी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहती हैं। संग्रहालय के अंदर स्थित रेस्तरां रात 9 बजे तक खुला रहता है।

असम में बाल विवाह के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन! राज्य में 500 से अधिक लोगों पर पुलिस का शिकंजा



बाल विवाह पर रोक के लिए असम पुलिस रोज कार्रवाई कर रही है। अब तक 500 से अधिक लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। असम में बाल विवाह के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है राज्यभर में 500 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की गई है धुबरी में सबसे ज्यादा लोग पकड़े गए हैं असम में बाल विवाह के खिलाफ प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। श्रीभूमि जिले में बाल विवाह के खिलाफ एक बड़े अभियान में पुलिस ने 28 मामले दर्ज किए हैं और 32 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 28 मुख्य अपराधी और चार सहायक शामिल हैं। एएसपी प्रणब ज्योति कलिता ने यह जानकारी दी। ऑपरेशन के बारे में बताते हुए, उन्होंने बताया कि बाल विवाह के अपराधियों और इसमें सहायता करने वालों को पकड़ने के लिए 26 अक्टूबर की रात को जिले के कई हिस्सों में एक विशेष अभियान चलाया गया था। पुलिस रिमांड के लिए आवेदन दिया उन्होंने यहां पत्रकारों को बताया कि बाल विवाह के खिलाफ 26 अक्टूबर की रात को एक विशेष अभियान चलाया गया था।

फिलीपींस में बिना नाम लिए पाकिस्तान को रक्षा मंत्री की दो टूक, ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण दिया



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिलीपींस में आतंकवाद को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने देश में सुरक्षा बढ़ाने और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई फिलीपींस में एडीएमएम-प्लस फोरम को संबोधित किया देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर आतंकवाद को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। गुरुवार को फिलीपींस के सेबू में आयोजित एडीएमएम-प्लस फोरम को संबोधित करते हुए राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने भारत में सुरक्षा बढ़ाने और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि आतंकवाद विरोधी क्षेत्र में भारत का अनुभव केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं है। बल्कि, यह दशकों से जमीनी स्तर पर सीमा पार सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने से प्राप्त हुआ है।

दिवाली से पहले किसानों को तोहफा, कल पीएम किसान की 24वीं किस्त जारी करेंगे PM मोदी

पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर को गुजरात से जारी होगी। 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 18,680 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक सहायता मिलने की जानकारी दी गई है। पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर को जारी होगी देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ मिलने की जानकारी है पात्र किसानों को सालाना 6,000 तीन किस्तों में दिए जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को गुजरात का दौरा करेंगे। इसी बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। पीएम मोदी कल अपने गुजरात दौरे के दौरान किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,680 करोड़ से ज्यादा



की राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। दौरे के पहले दिन वह बनासकांठा जिले के भीलडी में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे। वहीं, 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नर्मदा जिले के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। यह आयोजन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के मौके पर होगा। गुजरात के 52.33 लाख से अधिक किसानों को लाभ गुजरात के कृषि मंत्री जीतू वाघाणी ने बताया कि, पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त के तहत राज्य के 52.33 लाख से अधिक किसान परिवारों को 1,051 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने भीलडी में आयोजित होने वाले 'पीएम किसान उत्सव दिवस' कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के बाद यह जानकारी साझा की। PM किसान योजना में हर साल मिलते हैं 6,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 दिए जाते हैं। यह रकम 2,000 की तीन समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। कृषि मंत्री जीतू वाघाणी ने बताया कि योजना की पिछली 23 किस्तों के माध्यम से देशभर के किसानों को 4.47 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। गुजरात में भी अब तक लाभार्थियों को 24,137 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक सहायता मिल चुकी है। दो बायो-CNG प्लांट की आधारशिला रखेंगे PM पीएम किसान योजना की किस्त जारी करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनास डेयरी की ओर से थराद और राधनपुर में स्थापित किए जाने वाले दो कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) संयंत्रों का शिलान्यास भी करेंगे।

IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू यादव को राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने ED को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED को नोटिस जारी किया। IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। ईडी ने PMLA की धारा 5 के तहत 44.75 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती देने वाली RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें यह छूट भी दी है कि वे हाई कोर्ट में अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट से रोक (स्टे) की मांग कर सकते हैं। यह सुनवाई 3 दिसंबर को होनी है। लालू यादव ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को 10 सितंबर को चुनौती दी थी। अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज इससे पहले, 11 सितंबर को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक अहम फैसला सुनाया था। अदालत ने RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी उनके बेटे



तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दे दिया था। ईडी ने 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' (PMLA) के तहत इस मामले की जांच शुरू की थी। बता दें, कि यह जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा नई दिल्ली में दर्ज की गई एक FIR पर आधारित थी। आधिकारिक पद के दुरुपयोग का आरोप CBI ने जांच के तहत तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, पी.सी. गुप्ता और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता (IPC) और 'प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, 1988' की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। सीबीआई जांच के अनुसार, उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपने आधिकारिक पद का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने स्थापित नियमों की अनदेखी की और पुरी तथा रांची में रेलवे होटलों के विकास और संचालन का ठेका 'मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड' को दिया। लालू यादव और परिवार पर आरोप तत्काली रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने इसके बदले में, 'मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड' को बहुत कम कीमत पर 2 एकड़ जमीन मुहैय्या करायी और सौदा किया। इस कंपनी के मालिक और नियंत्रक लालू यादव के करीबी सहयोगी प्रेम चंद गुप्ता के परिवार के सदस्य थे। इतना ही नहीं बाद में, बहुत कम कीमत पर शेयर खरीदकर इस जमीन और कंपनी का पूरा कंट्रोल अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को सौंप दिया, जिससे की घूम-फिरकर इस जमीन का मालिकाना हक पूरी तरह से यादव परिवार के पास वापस आ गया।

ट्रोलिंग बंद करिए, अपना गढ़ संभालिए, PM मोदी को कांग्रेस का जवाब, नागपुर-वाराणसी में बड़ी हार की दिलाई याद

एमएलसी चुनाव में कांग्रेस की हार पर PM मोदी के तंज के बाद जयराम रमेश ने पलटवार किया। उन्होंने वाराणसी, नागपुर, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। MLC चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद, BJP की ट्रोलिंग पर जयराम रमेश का पलटवार। नागपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज और पटना में हारी भाजपा। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री को आत्म-मंथन करने की सलाह दी। MLC चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पार्टी और राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की। इसके जवाब में, सांसद जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को इसके बजाय अपने खुद के गढ़ की चिंता करनी चाहिए। जयराम रमेश ने अपने पीएम मोदी की तरह ही



सोशल मीडिया पर जवाब लिखा। उन्होंने एक्स पर लिखा, "प्रधानमंत्री को आत्म-मंथन करने की जरूरत है,लेकिन इसके बजाय, वे दूसरों को उपदेश दे रहे हैं!" अपने संसदीय क्षेत्र में क्यों हार गए पीएम मोदी? कांग्रेस सांसद ने उन्हें अपने और RSS के गढ़ की चिंता करने की सलाह देते हुए लिखा, "कांग्रेस की सीटों को गिनने से पहले, काश वे इस बात पर भी गौर करते कि उनके अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में BJP दोनों सीटें क्यों हार गई, और RSS के गढ़ नागपुर में कांग्रेस ने BJP को कैसे हरा दिया?" ट्रोलिंग बंद कीजिए BJP को ट्रोलिंग पर लगाम लगाने की सलाह देते हुए जयराम रमेश ने लिखा, "ट्रोलिंग बंद कीजिए। करोड़ों परिवार कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं, और निजी निवेश पूरी तरह रुक गया है। अहंकार छोड़िए और इन मुद्दों पर विचार कीजिए!" एमएलसी चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी को नागपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज और पटना में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ये ऐसे क्षेत्र है, जिसमें भाजपा की हार होना लगभग नामुमकिन था। इसके बावजूद पार्टी की हार होना भाजपा के लिए चिंता का विषय बन गई है। जनता ने पारित किया अविश्वास प्रस्ताव इस पर जयराम रमेश ने आगे लिखा कि जनता ने उनके खिलाफ अविश्वास दिखाया है। उन्होंने लिखा, "वाराणसी और नागपुर से लेकर लखनऊ, प्रयागराज और पटना तक, जनता ने आपकी नीतियों के खिलाफ स्पष्ट रूप से 'अविश्वास प्रस्ताव' पारित कर दिया है।" भाजपा के गढ़ में भाजपा की हार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में जिस तरह के नतीजे आए हैं, उसने एक साथ कई संदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को बढ़त हासिल है।

मजीठिया के खिलाफ 40 हजार पन्नों की चार्जशीट, AAP ने 736 करोड़ की मनी ट्रेल और BJP से कनेक्शन का किया दावा



पंजाब पुलिस की मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट पर केजरीवाल और सिसोदिया ने BJP को घेरा। आम आदमी पार्टी ने 736 करोड़ रुपये की ड्रग मनी का दावा किया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि अधिकतर नशा अब गुजरात से आता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मजीठिया को जेल में डाला। पंजाब पुलिस ने मजीठिया के खिलाफ 40,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की है। पंजाब में भगवंत मान सरकार पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर रही है। भगवंत मान की सरकार नशा फैलाने वाले मजीठिया जैसे नेताओं के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा उसी मजीठिया को साथ में लेकर गठबंधन करने की फिराक में है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि भाजपा इसके साथ पंजाब में नशे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने लगाए आरोप भाजपा की इस कोशिश पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संजयोजक अरविंद केजरीवाल समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

बैलेट बॉक्स, इस्तीफा दो से DK इट्स डन ब्रो तक, MLC चुनाव के नतीजों पर BJP ने कांग्रेस पर की मीम्स की बौछार



कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में BJP-JD(S) ने चारों सीटें जीतीं। इसके बाद BJP ने एक्स पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के खिलाफ मजाकियां अंदाज में चुटकी ली। 4 राज्यों में विधान परिषद चुनाव में अधिकतर सीटों पर कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला। भाजपा ने कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन पर चुटकी ली। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए मजाकिया पोस्ट शेयर किए। कर्नाटक विधान परिषद की चार सीटों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके सहयोगी दल जनता दल (सेक्यूलर) JD(S) ने सभी चार सीटों पर जीत हासिल की है। इसके बाद, BJP की कर्नाटक इकाई ने उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर तंज कसा।

स्वदेशी तेजस में अमेरिकी इंजन GE-404 क्यों? समझिए भारत के फाइटर जेट का पूरा गणित

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को मिले GE-404 इंजन तेजस Mk-1A फाइटर जेट के लिए अहम हैं। जानिए 97 विमानों के सौदे, इंजन की भूमिका और स्वदेशी तकनीक की खासियतें। काशी में 25 अक्टूबर को गंगा के ऊपर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अपनी गर्जना से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। नमो घाट पर आयोजित 'विंग्स ओवर गंगा' एयर शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल, सुखोई और अन्य विमानों का प्रदर्शन देखा। इस एयर शो ने वहां बैठी जनता को रोमांच और उत्साह से भर दिया। एयर शो में 100 से अधिक विमानों और हेलीकॉप्टरों के प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की गई थी। इसमें राफेल और सुखोई, तेजस समेत 52 लड़ाकू विमान शामिल बताए गए। लड़ाकू विमानों के साथ हेलीकॉप्टरों की समन्वित उड़ानों ने भी दर्शकों को



रोमांचित किया। गंगा के दोनों किनारों पर मौजूद लोगों की निगाहें लगातार आसमान पर टिकी रहीं। तेजस बनाने के लिए अमेरिकी इंजन का इस्तेमाल भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के साथ देश में तेजस के स्वदेशी निर्माण पर भी जोर दे रहा है। लेकिन स्वदेशी होने के बावजूद अभी भी इसे बनाने के लिए भारत को अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता है। सोचिए कि आप एक बहुत तेज रफ्तार वाली स्पोर्ट्स कार बना रहे हैं, लेकिन उसे चलाने के लिए आपको विदेश से इंजन आने का इंतजार करना पड़े। यह बिल्कुल उसी तरह है। तेजस बनाने के लिए एक GE-404 जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। भारत की प्रमुख सैन्य विमान निर्माता कंपनी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को एक अमेरिकी सप्लायर से अपना GE-404 जेट इंजन मिलता है। हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को चौथा इंजन मिला है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक, HAL को कुल 12 GE-404 इंजन मिलने की उम्मीद है। GE-404 जेट इंजन क्यों महत्वपूर्ण हैं? एक शक्तिशाली इंजन के बिना फाइटर जेट उड़ान नहीं भर सकता। ये GE-404 इंजन भारत में बने फाइटर जेट, 'तेजस LCA Mk-1A' के लिए 'दिल' की तरह काम करते हैं। इन इंजनों की लगातार सप्लाई मिलने से HAL अपनी निर्माण प्रक्रिया को तेज कर सकता है, ताकि वे समय पर भारतीय वायु सेना को ये फाइटर जेट सौंप सकें। तेजस LCA Mk-1A फाइटर जेट क्या है? तेजस LCA Mk-1A भारत में बना एक आधुनिक 'लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट' है। इन लड़ाकू विमानों की डिलीवरी 2027-28 में शुरू होगी और 6 सालों में अलग-अलग चरणों में पूरी होगी।

सम्पादकीय

ब्राजील के चुनाव परिणामों की व्याख्या

ब्राजील के मतदाताओं ने दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद को नकारते हुए लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण को चुना है। ब्राजील के नतीजों का असर अमेरिका और भारत पर भी पड़ेगा। ब्राज़ील के राष्ट्रपति चुनाव में दिग्गज वामपंथी नेता लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा की जीत किसी एक देश में होने वाली सामान्य तख्तापलट या किसी नेता की राजनीतिक वापसी मात्र नहीं है। यह लैटिन अमेरिका में तेज़ी से फैल रही धुर दक्षिणपंथी राजनीतिक लहर पर एक निर्णायक और रणनीतिक पलटवार है। कड़े मुकाबले वाले दूसरे दौर में, मौजूदा राष्ट्रपति लूला ने 51.79 प्रतिशत वोट (लगभग 64.2 मिलियन) हासिल कर पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे दक्षिणपंथी उम्मीदवार फ्लेवियो बोल्सोनारो (48.21 प्रतिशत) को हराया। 80 वर्षीय लूला अब ब्राज़ील के राष्ट्रपति के रूप में अपना चौथा कार्यकाल संभालेंगे। पहले दौर में बोल्सोनारो की बढ़त (47.03 प्रतिशत बनाम लूला के 45.16 प्रतिशत) को देखते हुए, दूसरे दौर में लूला की ज़बरदस्त जीत लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिरता, श्रमिकों के हितों, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इस परिणाम की गूंज वाशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स और नई दिल्ली तक सुनाई दे रही है। हाल के वर्षों में, आक्रामक, व्यक्तिवादी और दक्षिणपंथी राजनीतिक ताकतों ने दक्षिण अमेरिका में व्यवस्थित रूप से अपना प्रभाव फैलाया है। वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआत के बाद से, लैटिन अमेरिका को केवल एक पड़ोसी क्षेत्र के बजाय निर्विवाद प्रभाव क्षेत्र (मोनरो सिद्धांत की परंपरा में) के रूप में स्थापित करने का ज़ोरदार प्रयास किया गया है। इस रणनीति के तहत, वाशिंगटन ने अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, अल सल्वाडोर, पेरू, इक्वाडोर और कोस्टा रिका जैसे देशों में दक्षिणपंथी, अति-दक्षिणपंथी, नवउदारवादी और ट्रम्प समर्थक सरकारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया है। परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में सत्तावादी शासन की ओर झुकाव रखने वाली दक्षिणपंथी पार्टियों का प्रभाव काफी बढ़ गया है। ब्राज़ील लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाला देश है। फ्लेवियो बोल्सोनारो न केवल मौजूदा राष्ट्रपति लूला के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी थे, बल्कि ट्रंप के कट्टर समर्थक और अपने पिता जैर बोल्सोनारो की विवादास्पद राजनीतिक विरासत के वाहक भी थे। यदि बोल्सोनारो जूनियर निर्वाचित हो जाते, तो ट्रंप प्रशासन को पूरे महाद्वीप में अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को साधने के लिए एक बहुत शक्तिशाली सहयोगी मिल जाता। लूला की जीत ने ट्रंप की "दक्षिणी नीति" और लैटिन अमेरिका में दक्षिणपंथी राजनीतिक विस्तार को करारा झटका दिया है। पिछले चार दशकों से दुनिया भर में बेरहमी से लागू किए गए बेलगाम नवउदारवादी आर्थिक मॉडल ने वैश्विक स्तर पर गहरा असंतोष पैदा किया है। बाज़ार का असीमित उदारीकरण, सार्वजनिक खर्च में कटौती, अनियंत्रित निजीकरण, श्रम कानूनों का कमज़ोर होना और 'ट्रिकल डाउन' सिद्धांत पर आधारित अर्थव्यवस्था ने पूंजी का केंद्रीकरण तो किया ही है, साथ ही गरीबी और असमानता में भी भारी वृद्धि की है। इन आर्थिक झटकों से न केवल विकासशील देश प्रभावित हुए हैं, बल्कि विकसित यूरोपीय और अमेरिकी समाजों का मध्यम वर्ग भी बढ़ती मुद्रास्फीति, नौकरी की असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अभाव से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई देशों में, धुर दक्षिणपंथी, आप्रवासी-विरोधी और विभाजनकारी राजनीति ने इस असंतोष को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। ऐसे अंतरराष्ट्रीय माहौल में, लूला की जीत कल्याणकारी अर्थशास्त्र का एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत करती है। अपने पिछले कार्यकाल में, लूला ने 'बोल्सा फ़ैमिलिया' जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करके लाखों ब्राज़ीलियाई लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था। यह जीत श्रमिकों, वंचितों और मध्यम वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा को अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाने की जनभावना का समर्थन करती है। वामपंथियों की जीत का मतलब नवउदारवाद का तत्काल अंत नहीं है; हालांकि, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए सामाजिक न्याय के मॉडल को कैसे लागू किया जा सकता है, इसकी परीक्षा अब लूला के प्रशासन में ही होगी। लूला की वापसी से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और मजबूत होगी। लूला को एक स्वतंत्र और संप्रभु विदेश नीति का समर्थक माना जाता है, जो किसी एक महाशक्ति के दावों से बंधी नहीं है। वे विकासशील देशों के आर्थिक और रणनीतिक हितों को दृढ़ता से साधते हैं, साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर पश्चिमी वर्चस्व के दबाव को संतुलित करते हैं। स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाना, ब्रिक्स समूह का विस्तार करना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे पश्चिमी शैली के वित्तीय संस्थानों का लोकतंत्रीकरण करना अब गति पकड़ेगा। ब्राजील में सत्ता का यह परिवर्तन भारत के लिए बेहद सकारात्मक और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत और ब्राजील ब्रिक्स, आईबीएसए और जी-20 में महत्वपूर्ण साझेदार हैं। दोनों देशों के सामने गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसी समान चुनौतियां हैं। लूला के नेतृत्व में ब्राजील जैव ईंधन, कृषि प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग को और गहरा कर सकता है। जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में जलवायु वित्त और समृद्ध देशों से विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे मुद्दों पर भारत और ब्राजील वैश्विक दक्षिण का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। भारत को इस परिणाम को अमेरिका-विरोधी नजरिए से नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और उभरते रणनीतिक साझेदार के रूप में देखना चाहिए। इस चुनाव का सबसे संवेदनशील पहलू पर्यावरण का मुद्दा है।

पॉक्सो अधिनियम में सुधार आवश्यक

हाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर निर्णय देते हुए पोक्सो अधिनियम, 2012 के कठोर अनुप्रयोग और भारत की सामाजिक वास्तविकताओं के बीच संबंध पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। यह मामला ऐसे व्यक्ति से जुड़ा था, जिसके विरुद्ध पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लड़की के माता-पिता ने यह कहते हुए मामला दर्ज कराया था कि उनकी बेटी नाबालिग है, जबकि लड़की ने न्यायालय के समक्ष अपने साथी के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की थी। न्यायालय ने सामाजिक परिस्थितियों, अशिक्षा और गरीबी जैसी कठोर वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए कहा, 'पोक्सो अधिनियम का क्रियान्वयन कुछ तथ्यात्मक परिस्थितियों में ऐसे परिणाम उत्पन्न कर सकता है, जो न्याय के बजाय अन्याय को बढ़ावा देने वाले प्रतीत हों।' न्यायालय ने विधि आयोग से अधिनियम में संभावित संशोधनों पर विचार करने का अनुरोध किया, ताकि असाधारण परिस्थितियों में विशेष न्यायाधीशों को सजा निर्धारित करने में अधिक विवेकाधिकार देने की संभावना पर विचार किया जा सके। कुछ समय पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अनिरुद्ध एवं अन्य' मामले में भी पोक्सो अधिनियम के दुरुपयोग से जुड़े प्रश्नों पर विचार किया था। यह मामला लगभग 12 वर्ष की एक लड़की की मां द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी से संबंधित था, जिसमें लड़की को घर से ले जाने का आरोप लगाया गया था। आरोपित को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में किशोर संबंधों के संदर्भ में पोक्सो अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, 'इस निर्णय की एक प्रति भारत सरकार के विधि सचिव को भेजी जाए, ताकि इस समस्या पर अंकुश लगाने के लिए यथासंभव कदम उठाने पर विचार किया जा सके। इन कदमों में अन्य उपायों के साथ-साथ एक ऐसे 'रोमियो–जूलियट प्रविधान' को शामिल करने की संभावना भी हो, जो किशोर संबंधों को इस कानून के कठोर प्रभाव से मुक्त करे। साथ ही ऐसी व्यवस्था बनाने पर भी विचार किया जाए, जिसके माध्यम से उन व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन चलाया जा सके, जो इन कानूनों का उपयोग आपसी हिसाब चुकता करने अथवा बदला लेने के लिए करते हैं।' सर्वोच्च न्यायालय की यह चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि विधिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य समाज का संरक्षण और न्याय की स्थापना करना है। किशोरावस्था में लिए गए निर्णयों और उनसे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया का प्रभाव किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, शिक्षा और भविष्य पर पड़ सकता है। इसी संदर्भ में 2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 'अतुल मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं तीन अन्य' मामले में कहा था कि किशोरावस्था में परस्पर आकर्षण के कारण लिए गए निर्णय आवेगपूर्ण और अपरिपक्व हो सकते हैं, लेकिन उन्हें केवल इसी आधार पर पाप या कलंकित नहीं माना जाना चाहिए। पोक्सो अधिनियम के कठोर प्रविधानों को बिना परिस्थितियों पर पर्याप्त विचार किए लागू करने से किशोरों की प्रतिष्ठा और भविष्य को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है। किशोरावस्था में एक-दूसरे के प्रति आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव विकसित होना स्वाभाविक है। इस अवस्था में विकसित होने वाला प्रत्येक संबंध किसी अनुचित मंशा का प्रमाण नहीं होता। कई बार किशोर भावनाओं और आकर्षण को समझते हुए एक-दूसरे के निकट आते हैं, जबकि संबंधों की जिम्मेदारियों और उनके दूरगामी परिणामों को समझने की उनकी क्षमता अभी विकसित हो रही होती है। इसलिए ऐसे संबंधों का मूल्यांकन करते समय केवल उम्र या संबंध की प्रकृति को आधार बनाने के बजाय उनकी परिस्थितियों, आपसी व्यवहार तथा दबाव अथवा शोषण की उपस्थिति को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। भारतीय समाज में किशोरों के प्रेम-संबंधों का प्रश्न व्यक्तिगत भावनाओं से कहीं आगे जाकर पारिवारिक मान्यताओं, सामाजिक प्रतिष्ठा और परंपरागत मूल्यों से जुड़ जाता है। एक ओर किशोरावस्था में विकसित होती भावनात्मक स्वतंत्रता और अपनी पसंद के अनुसार संबंध चुनने की आकांक्षा है तो दूसरी ओर परिवार और समुदाय की अपेक्षाएं, जिनमें जाति, पंथ और विवाह संबंधी परंपराओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन दोनों के बीच टकराव की स्थिति में किशोरों के संबंध कभी-कभी पारिवारिक विवाद और सामाजिक तनाव का कारण बन जाते हैं। अनेक बार परिवार की असहमति ऐसे संबंधों को स्वीकार करने के बजाय उनका विरोध करने का रूप ले लेती है और मामला कानूनी टकराव तक पहुंच जाता है। ऐसे में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो उठता है कि बालकों को यौन शोषण और दुर्व्यवहार से संरक्षण देने के लिए निर्मित कानून का उपयोग वास्तविक अपराधों और पारिवारिक असहमति से उपजे विवादों के बीच अंतर को किस सीमा तक पहचान पाता है।

किशोरावस्था की भावनाओं को अपराध की भाषा में समझने से पहले उनकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वास्तविकताओं को समझना आवश्यक है। बाल संरक्षण का उद्देश्य किसी भी प्रकार के शोषण से बच्चों को सुरक्षित रखना है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया में उनके भविष्य और गरिमा की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

प्रदूषण के खिलाफ लड़नी होगी साझा लड़ाई

सर्दियों की आहट के साथ ही उत्तर भारत के क्षितिज पर छाने वाली गहरी धुंध और धुएं की परत अब महज एक मौसमी घटनाक्रम तक सीमित नहीं नहीं रह गया, बल्कि यह करोड़ों नागरिकों के लिए एक गंभीर और जानलेवा जन-स्वास्थ्य आपातकाल बन चुका है। अक्टूबर से फरवरी के बीच दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) अक्सर 400 से 450 के खतरनाक स्तर को पार कर जाता है। जैसे ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 'खराब' या 'गंभीर' श्रेणी में प्रवेश करता है, प्रशासनिक तंत्र में अचानक अप्रत्याशित गहमा-गहमी दिखाई देने लगती है। आनन-फानन में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के विभिन्न प्रविधानों को लागू कर दिया जाता है। निर्माण कार्यों पर पाबंदी, निर्माण स्थलों पर एंटी-स्माग गन की तैनाती, डीजल जेनरेटरों के इस्तेमाल पर रोक और सड़कों पर पानी के छिड़काव जैसे उपाय कागजों और मीडिया की सुर्खियों में तैरने लगते हैं। जबकि वायुमंडलीय विज्ञान और भूगोल के मौलिक नियमों की दृष्टि से देखें, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या केवल एक महानगर या कुछ चुनिंदा जिलों की सीमाओं में सिमटी दंडात्मक और तात्कालिक कार्रवाइयां इस विकराल वायुमंडलीय संकट का वास्तविक और स्थायी समाधान दे सकती हैं? हवा, गैसों और सूक्ष्म कणों (पीएम 2.5 और पीएम 10) की कोई प्रशासनिक, राजनीतिक या भौगोलिक सीमा नहीं होती। उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों के आसमान में तैरने वाला जहर केवल वहां के स्थानीय वाहनों के धुएं या औद्योगिक चिमनियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह पूरे वृहद इंडो-गंगा मैदानी इलाकों के संयुक्त उत्सर्जन और वायुमंडलीय गतिशास्त्र से निर्धारित होता है। ऐसे में किसी एक शहर द्वारा अलग-थलग होकर उठाए गए एकांगी कदम इस बड़े संकट के सामने वैसे ही निष्प्रभावी साबित होते हैं, जैसे उफनती नदी के मुहाने पर पत्तों का बांध बनाना। हालिया वायु गुणवत्ता आंकड़ों का सूक्ष्म वैज्ञानिक विश्लेषण इस भ्रांति को पूरी तरह से तोड़ देता है कि प्रदूषण केवल दिल्ली-एनसीआर की विशिष्ट समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएम 2.5 का वार्षिक औसत स्तर पांच माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में यह स्तर अक्सर 80 से 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक दर्ज किया जाता है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में अब अकेले दिल्ली का नाम दर्ज नहीं है, बल्कि गंगा के मैदानी भूभाग में बसे तमाम शहर इस विषैले चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, हापुड़ से लेकर हरियाणा के रोहतक, हिसार और राजस्थान के औद्योगिक शहर कोटा तक की वायु गुणवत्ता लगातार 'बेहद खराब' और 'अत्यंत गंभीर' स्तर पर बनी हुई है। उत्तर भारत का एक क्षेत्र भौगोलिक रूप से एक विशाल प्राकृतिक कटोरे के समान है। सर्दियों के आगमन के साथ जब तापमान में गिरावट आती है, तो हवा का घनत्व बढ़ जाता है और उसकी गति मंद पड़ जाती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे थर्मल इन्वर्जन या वायुमंडलीय व्युत्क्रमण कहते हैं, जिसमें गर्म हवा की ऊपरी परत ठंडी और भारी हवा को नीचे धरातल के पास ही दबाकर रख लेती है। इस प्राकृतिक जाल में जब उद्योगों, वाहनों, धूल और पराली का धुआं आकर मिलता है, तो यह संपूर्ण बेल्ट एक विशालकाय गैस चैंबर का रूप धारण कर लेती है। जब संकट का क्षेत्र संपूर्ण उत्तर भारत है, तो इसका समाधान किसी एक नगर निगम या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हो ही नहीं सकता। इसके लिए संपूर्ण एयरशेड पर आधारित एक एकीकृत और समेकित क्षेत्रीय रणनीति की आवश्यकता है। वार्षिक वायुमंडलीय संकट का एक प्रमुख और विवादास्पद जैविक कारक कृषि अवशेषों यानी पराली का दहन है। पराली दहन से होने वाला उत्सर्जन उत्तर-पश्चिमी हवाओं की सवारी करता हुआ पूरे उत्तर भारत के आसमान को अपने आगोश में ले लेता है। चूंकि पराली संकट कृषि अर्थशास्त्र, ऊर्जा नीति और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़ा एक बहुआयामी मुद्दा है, इसलिए इसमें केंद्र सरकार का सीधा, आर्थिक और नीतिगत हस्तक्षेप अनिवार्य है। इसके लिए फसल विविधीकरण से लेकर उचित प्रौद्योगिकियों के लिए भारी सब्सिडी और बायो-मेथेनेशन प्लांट्स जैसा स्थायी बुनियादी ढांचा समय की आवश्यकता है, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि प्रदूषण में केवल पराली का योगदान नहीं है। प्रदूषण की समस्या से ग्रस्त दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान की सरकारों के बीच आवश्यक तालमेल का अभाव भी स्थितियों को बिगाड़ता है। संकट की दस्तक और उसके गहराते ही राजनीतिक दल और विभिन्न राज्य सरकारें दोषारोपण का खेल शुरू कर देती हैं। जबकि वायु प्रदूषण जैसी राष्ट्रीय आपदा पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर साझा राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देना आज की सबसे बड़ी मांग है।

अन्नू कपूर के कमेंट्स पर तमन्ना भाटिया ने किया रिएक्ट, बोली- मैं अपने काम पर करती हूं फोकस

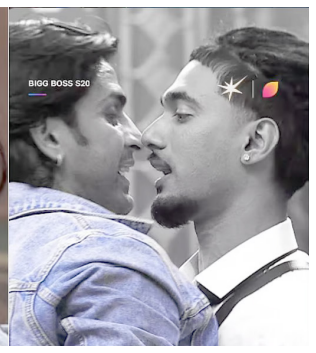




तमन्ना भाटिया ने अन्नू कपूर के लुक्स पर किए गए विवादित कमेंट्स पर प्रतिक्रिया दी है। अभिनेत्री ने कहा कि वह ऐसी बातों में उलझने के बजाय अपने अभिनय पर ध्यान देना पसंद करती हैं। एकता कपूर की फिल्म वन से हाल ही में दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाली तमन्ना भाटिया ने अन्नू कपूर के विवादित कमेंट्स पर रिएक्ट किया है। साल 2025 में अन्नू कपूर ने तमन्ना भाटिया के रंग-रुप को लेकर विवादित बयान दिया था। साल 2025 में किए गए इस बयान के बाद जब तमन्ना भाटिया से इसको लेकर सवाल किया, तो तमन्ना ने भी काफी समझदारी से बयान दिया। मीडिया इंटरव्यू के दौरान तमन्ना भाटिया से जब बारे में सवाल किया गया, तो तमन्ना ने इस बारे में खुलकर बात की है। उनसे अन्नू कपूर की ओर से उनके रंग और शारीरिक बनावट को लेकर की गई टिप्पणियों के बारे में पूछा गया था। सबसे जरुरी काम सुनना है तमन्ना भाटिया ने इस मीडिया इंटरव्यू के दौरान कहा कि एक क्रिएटिव इंसान के तौर पर, हमारा काम सिर्फ सुनना है। जब हम सुनते हैं, तो हम क्या लेकर चलते हैं और क्या फिल्टर करते हैं, ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तमन्ना ने आगे कहा कि अगर लोग इस तरह की बातों को जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगें, तो उनके लिए जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। काम पर फोकस करने को देती हूं महत्व तमन्ना ने इस मीडिया इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं इन चीजों को देखती भी नहीं हूं। मैं अपने काम पर फोकस करती हूं। मैं इस पर फोकस करती हूं कि मैं क्या बनाना चाहती हूं। मैं अपने एक्टिंग करियर पर फोकस करती हूं। उन्होंने आगे कहा कि अपने काम को केवल करियर बनाने का जरिया नहीं, बल्कि एक सेवा के रूप में देखने की बात भी कही। उनके अनुसार, जब काम सही भावना से किया जाता है, तो वह लोगों तक पहुंचता है। क्या था अन्नू कपूर का विवादित बयान? यह विवाद साल 2025 में उस समय शुरू हुआ, जब अन्नू कपूर शुभांकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू में पहुंचे थे। बातचीत के दौरान उन्हें फिल्म स्त्री 2 के गाने आज की रात में तमन्ना भाटिया के परफॉर्मेंस की एक क्लिप दिखाई गई। होस्ट ने एक्ट्रेस की तारीफ की, जिसके बाद अन्नू कपूर ने उनके लुक्स पर टिप्पणी करते हुए दूधिया बदन शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने बयान को आशीर्वाद से जोड़ते हुए कहा कि अगर उनके गाने से बच्चों को अच्छी नींद आती है, तो यह देश के लिए अच्छी बात होगी। हालांकि, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस टिप्पणी की आलोचना की। उनका कहना था कि अभिनेत्री की परफॉर्मेंस की तारीफ करने के बजाय उनके शारीरिक रूप-रंग पर ध्यान दिया गया।

कप्तानी कार्य में बिग बॉस के घर में मचा घमासान, यंग डीएसए और गूल्लू के बीच हो गई हाथापाई





बिग बॉस 20 के आज के एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क के दौरान यंग, गुल्लू और स्काउट OP के बीच विवाद देखने को मिल सकता है। वहीं माही विज और काजी तौकीर की बहस के बाद घर में भावुक माहौल बन जाएगा।

कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 20 में आज का एपिसोड काफी ड्रामे से भरपूर रहने वाला है। जहां एक ओर कप्तानी की दावेदारी के लिए सभी घरवाले अपनी जान झोंक देंगे, तो वहीं यंग और स्काउट की दोस्ती में भी दरार आते हुए दिख सकती है। बिग बॉस में आज का दिन पूरा लड़ाई झगड़े से भरपूर रहने वाला है। जहां एक ओर कैप्टनसी टास्क के दौरान यंग डीएसए और गूल्लू के बीच जोरदार लड़ाई देखने के लिए मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर माही विज की भी काजी तौकीर और आम्रपाली के साथ झगड़ा होगा। हालांकि इस दौरान यंग डीएसए और स्काउट के बीच में भी बहस होती हुई नजर आने वाली है।

स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड के सपोर्ट में उतरी गौहर खान, बोली- काश्वी को गलत न ठहराएं

बिग बॉस 20 में लव गिल और स्काउट के बीच बढ़ते तनाव पर गौहर खान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने काजी तौकीर की समझदारी की तारीफ करते हुए लव, स्काउट और काश्वी को लेकर अपनी राय रखी। कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 20 में वीकेंड के वार के दौरान लव गिल और स्काउट ओपी के बीच में काश्वी हीरानंदानी की एंट्री से शो का माहौल काफी बदल गया है। बिग बॉस 20 में हाल ही में हुए वीकेंड का वार विवाद पर बिग बॉस 7 की विनर रही गौहर खान ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर लव गिल और स्काउट ओपी को नॉर्मल रहने की सलाह दी है। काजी तौकीर की जमकर की तारीफ दरअसल, हाल ही में बिग बॉस 20 के वीकेंड का वार में काश्वी ने स्काउट और लव गिल की नजदीकियों पर सवाल उठाए थे, उसके बाद घर के सदस्य काज़ी तौकीर ने इस पूरे बयान और स्थिति को बेहद मैच्योरिटी और इंसानियत के साथ संभाला और समझाया था। हालांकि घर के अन्य सदस्य अक्सर काज़ी को बुरा-भला कहते हैं, लेकिन इस घटना के बाद काजी ने स्काउट और लव दोनों के प्रति सहानुभूति दिखाई। काजी के इस तरह के व्यवहार को देखते हुए अभिनेत्री गौहर खान ने उनकी तारीफ की। लव गिल और स्काउट को दी





सलाह गौहर खान ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा कि स्काउट और लव गिल को सबसे सही और लॉजिकल सलाह काजी ने दी। पता नहीं सब ऐसे मातम क्यों मना रहे हैं कि स्काउट को अपनी गर्लफ्रेंड की कही हुई बात माननी चाहिए। काश्वी ने तो लॉजिक बताया था कि कट ऑफ करो। मतलब कि पहले की तरह की क्लोजनेस मत रखो। बिग बॉस से की लव गिल को काश्वी की माफी दिखाने की मांग गौहर खान ने बिग बॉस से गुजारिश की है कि वे लव गिल को काश्वी द्वारा मांगी गई माफी भी दिखा दें। उन्होंने कहा कि काश्वी द्वारा मांगी गई माफी लव गिल को इसलिए दिखाना जरूरी है, क्योंकि यह देखकर लव को अच्छा लगेगा कि बाहर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि काश्वी ने सच स्वीकार कर लिया है कि उसने सारा इल्जाम लव पर डाल दिया था और दूसरी बात काजी ने बिल्कुल सही बोला है कि काश्वी ने बात करने के लिए मना नहीं किया है, बल्कि उसने मसाज और ज्यादा करीब होने के लिए मना किया है। अगर काजी और लव बातें करना बंद कर देंगे तो लोगों और गलत लगेगा। काश्वी को गलत नहीं बोलने की कही बात उन्होंने कहा कि लोग बातें बनाएंगे कि अगर बात नहीं कर रहे हैं तो कैसे भाई-बहन है। दोनों की नीयत ठीक नहीं है।

दोनों एक दूसरे को भाई बहन बोलते हैं तो बात कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अभिनेत्री ने काश्वी का समर्थन करते हुए कहा कि प्लीज काश्वी को भी गलत मत बोलिए और न ही लव और स्काउट को गलत बोलें, क्योंकि कभी-कभी हमें घर के माहौल में ज्यादा बातें समझ आती नहीं हैं और मुझे लगता है कि स्काउट और लव को थोड़ा समय देना चाहिए और काजी आपका धन्यवाद, आपने इस बात को ठीक से समझाया।

2 बार भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, कल होगा पहला हाई-वोल्टेज महामुकाबला; कहां देखें लाइव मैच?



क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगले 10 दिन के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच 2 महामुकाबले होने जा रहे हैं। जानिए कब, कहां और कैसे देख सकेंगे लाइव मैच। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में शुक्रवार को होगा भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला दोनों टीमों के मैच हांगकांग के मोंग कोक स्थित 'मिशन रोड ग्राउंड' पर खेला जाएगा दूसरा मुकाबला अंडर-19 एशिया कप 2026 के तहत खेला जाएगा क्रिकेट के मैदान पर जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होती हैं, तो रोमांच अपने चरम पर पहुंच जाता है।

अभिषेक शर्मा बने दुनिया के नंबर-1 T-20 बल्लेबाज, मार्को यानसन ने टेस्ट में रचा इतिहास



अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं। वहीं, टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के मार्को यानसन ने रवींद्र जडेजा और मिचेल स्टार्क को पछाड़कर इतिहास रच दिया है। ICC T20 रैंकिंग में अभिषेक शर्मा बने दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज मार्को यानसन ने रवींद्र जडेजा और मिचेल स्टार्क को पछाड़कर रचा इतिहास भारत के चार बल्लेबाज टॉप-10 सूची में जगह बनाने में कामयाब भारतीय क्रिकेट टीम के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने आईसीसी की ताजा टी-20 रैंकिंग में इतिहास रच दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मैच में शानदार शतक जड़ने वाले अभिषेक शर्मा दुनिया के नंबर-1 टी-20 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ईशान किशन को पीछे छोड़ा है, जो चोट के कारण पिछले कुछ मैचों से बाहर रहने की वजह से दो पायदान फिसलकर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। टॉप-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज, फिर भी सन्नाटा ताजा टी-20 रैंकिंग के अनुसार, भारत के चार बल्लेबाज टॉप-10 सूची में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि, गेंदबाजों और ऑलराउंडर्स की टॉप-10 लिस्ट में भारत का कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं है। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान दुनिया के नंबर-1 टी-20 गेंदबाज बने हुए हैं, जबकि जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा नंबर-1 ऑलराउंडर की कुर्सी पर काबिज हैं। ईशान को चोट का नुकसान, फरहान को मिला फायदा पिछले हफ्ते तक रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा और तीसरा टी-20 मुकाबला नहीं खेल सके। उनकी इस इंजरी का सीधा फायदा पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को मिला, जिन्होंने 13 अक्टूबर के बाद से कोई मैच नहीं खेला है। किशन के अंक कटने की वजह से वह अब तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। अक्षर पटेल फिसले, बुमराह को मिला आराम भारतीय गेंदबाजों के लिए यह रैंकिंग अच्छी नहीं रही। ऑलराउंडर अक्षर पटेल एक स्थान फिसलकर 11वें नंबर पर आ गए हैं, जिससे टॉप-10 में अब कोई भी भारतीय गेंदबाज नहीं है।

क्या अरब पार्टियां इजराइल में नेतन्याहू को हटाने में मदद कर सकती हैं? यह कितना आसान है

इजरायल चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू और विपक्षी गठबंधन बहुमत से दूर हैं। अरब पार्टियों को 19 सीटें मिलने का अनुमान है। अब सरकार गठन का भविष्य उनके सहयोग पर निर्भर करेगा। इजरायल चुनाव में नेतन्याहू और विपक्ष, दोनों बहुमत से दूर। जॉइंट लिस्ट और राम पार्टी को मिलाकर 19 सीटें मिलने का अनुमान। सरकार गठन में अरब पार्टियों की भूमिका अहम, नए चुनाव की भी संभावना। इजरायल में आम चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक संकट की स्थिति पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गठबंधन और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन, दोनों में से किसी को भी सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सीटें नहीं मिली हैं। ऐसे में इजरायल की दो अरब-बहुल पार्टियां सत्ता गठन की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा सकती हैं। बुधवार तक करीब 86 से 90 फीसदी मतों की गिनती के बाद केंद्रीय चुनाव समिति के आंशिक नतीजों में नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें और आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलने का अनुमान था। वहीं, जॉइंट लिस्ट और राम पार्टी को मिलाकर 19 सीटें मिलने की संभावना जताई गई। इनमें जॉइंट लिस्ट को 12 और राम को सात सीटें मिल सकती हैं। इजरायल की 120 सदस्यीय संसद यानी नेसेट में अरब पार्टियों का यह अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त प्रदर्शन माना जा रहा है। अरब पार्टियों को कैसे मिलीं इतनी सीटें? अरब पार्टियों की बढ़त के पीछे अरब समुदाय के मतदाताओं की बढ़ी भागीदारी को अहम कारण माना जा रहा है। केंद्रीय चुनाव समिति के



अनुसार, कुल मतदान कम से कम 77.7 फीसदी रहा, जो 1999 के बाद किसी संसदीय चुनाव में सबसे अधिक है। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक, अरब समुदाय में मतदान करीब 80 फीसदी तक पहुंच गया। अरब समुदाय के मतदाताओं में सरकार और उसके दक्षिणपंथी मंत्रियों के प्रति नाराजगी को भी इसकी वजह माना जा रहा है। समुदाय लंबे समय से संगठित अपराध, आवास की कमी, भेदभाव और सरकारी निवेश की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। वर्ष 2025 में अरब नागरिकों की हत्या के 252 मामले सामने आने का एक अनुमान भी दिया गया था। अरब पार्टियों की सफलता से नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके गठबंधन को पिछली संसद में 68 सीटें हासिल थीं, लेकिन इस बार उसे करीब 15 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। क्या हैं अरब पार्टियों के राजनीतिक समीकरण? जॉइंट लिस्ट में कम्युनिस्ट विचारधारा वाली हदाश, अरब राष्ट्रवादी तआल और फिलिस्तीनी राष्ट्रवादी बलाद शामिल हैं। यह गठबंधन आमतौर पर यहूदी नेतृत्व वाली सरकारों में शामिल होने से बचता रहा है। इसके नेता अहमद तिबी और यूसुफ जबरीन विपक्ष के साथ मिलकर नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार में सीधे शामिल होने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। दूसरी ओर, मंसूर अब्बास के नेतृत्व वाली राम पार्टी ने 2021 में बेनेट-लैपिड सरकार में शामिल होकर इतिहास बनाया था। यह किसी इजरायली गठबंधन सरकार में शामिल होने वाली पहली स्वतंत्र अरब पार्टी बनी थी। अब्बास ने संकेत दिया है कि यदि आइजेनकोट के नेतृत्व में सरकार बनने की संभावना मजबूत होती है, तो उनकी पार्टी उसमें शामिल हो सकती है। राम पार्टी अरब समुदाय में अपराध पर नियंत्रण और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ठोस कदम चाहती है। दोनों अरब पार्टियां आवास, भेदभाव और सरकारी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी प्रतिबद्धताएं मांग सकती हैं। नेतन्याहू और विपक्ष के सामने क्या चुनौती? नेतन्याहू ने अरब पार्टियों के समर्थन से बनने वाली सरकार को शर्मनाक बताया है। उनकी पार्टी लिकुड ने चुनाव में कथित अनियमितताओं के आरोप भी लगाए हैं, हालांकि चुनाव अधिकारियों को अब तक बड़े पैमाने पर मतों में हेरफेर का प्रमाण नहीं मिला है।

नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को बड़ा झटका, इजरायल पुलिस ने खारिज किया वोट चोरी का आरोप, कहा- कोई ठोस सबूत नहीं



इजरायल पुलिस ने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के अरब दलों पर लगाए गए चुनावी धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस ने कहा कि दावों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं हैं। इजरायल पुलिस ने लिकुड पार्टी के चुनावी धांधली के आरोप खारिज किए पुलिस के मुताबिक, दावों के समर्थन में ठोस सबूत नहीं मिले लिकुड पार्टी 53 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी इजरायल पुलिस ने गुरुवार को सत्ताधारी लिकुड पार्टी के अरब पार्टियों पर लगाए 'चुनाव चोरी' के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी ने धांधली का आरोप लगाते हुए पूरी प्रक्रिया की जांच कराने की मांग उठाई थी। लिकुड पार्टी ने दावा किया था कि उनके पास इसे लेकर सैकड़ों लोगों की गवाही मौजूद है। इन आरोपों की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी समर्थन किया है। 'द यरूशलम पोस्ट' के मुताबिक, इस मामले में बयान जारी कर पुलिस ने अपनी बात रखी। पुलिस ने कहा, मतदान के दिन चुनावी निष्पक्षता से जुड़ी कुछ असामान्य घटनाएं हुईं, लेकिन पिछली बार के चुनावों की तुलना में इनकी संख्या काफी कम थी। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि इन दावों के समर्थन में कोई जांच संबंधी या खुफिया सबूत नहीं हैं। अरब समुदाय ने किया रिकॉर्ड मतदान इससे पहले बुधवार को, सेंट्रल इलेक्शन कमिटी (CEC) के एक अधिकारी ने भी धोखाधड़ी के इन दावों को खारिज कर दिया था। इजरायल में अभी वोटों की गिनती चल रही है, लेकिन मंगलवार को हुए चुनाव में अरब पार्टियों ने 19 सीटें जीत ली हैं। इस चुनाव में अरब समुदाय की ओर से रिकॉर्ड मतदान देखने को मिला। गुरुवार सुबह तक आधिकारिक मतगणना 91% तक पहुंच गई थी। इसमें केवल 'डबल-लिफाफे' वाले मतपत्र शामिल नहीं थे, जिनकी गिनती पूरी रात चलने वाली थी। सबसे बड़ी दल बनी लिकुड पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधवार शाम को बताया था कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गुट अपनी बढ़त बनाए हुए है और अगली नेसेट (संसद) में लिकुड पार्टी को 53 सीटें मिली हैं, जबकि विपक्षी गुट को 48 सीटें मिली हैं।

पाकिस्तान के थारपारकर में दर्दनाक हादसा, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से 9 की मौत, मची अफरा-तफरी

पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थारपारकर में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से गर्भवती महिला समेत 9 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं। पाकिस्तान के थारपारकर में एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर फटा। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से गर्भवती महिला समेत 9 लोगों की मौत हो गई। एम्बुलेंस में उस समय आग लग गई, जब कर्मचारी ऑक्सीजन सिलेंडर बदल रहे थे। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थारपारकर जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की खबर सामने आई है। इस दर्दनाक हादसे में एक गर्भवती महिला समेत 9 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान में यह धमाका एक हेल्थ सेंटर में खड़ी एम्बुलेंस के अंदर हुआ। बचाव दल के अधिकारियों के अनुसार, घायलों में से एक व्यक्ति की मौत कराची ले जाते समय रास्ते में ही हो गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार, बचाव दल के अधिकारियों ने बताया



कि थारपारकर के नागरपारकर तालुका के डानो धंधल में 'पीपल्स प्राइमरी हेल्थकेयर इनिशिएटिव' (PPHI) की एक एम्बुलेंस में उस समय आग लग गई, जब कर्मचारी ऑक्सीजन सिलेंडर बदल रहे थे। हेल्थ सेंटर में खड़ी थी एम्बुलेंस नागरपारकर के असिस्टेंट कमिश्नर ने इस हादसे की पुष्टि की। कमिश्नर के अनुसार, जब धमाका हुआ, तब एम्बुलेंस हेल्थ सेंटर में खड़ी थी। अस्पताल प्रशासन और बचाव दलों ने बताया कि जब कर्मचारी ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रहे थे, तब एम्बुलेंस के अंदर एक गर्भवती महिला मौजूद थी। ऑक्सीजन सिलेंडर में अचानक हुए धमाके के कारण एम्बुलेंस में भयंकर आग लग गई। पुलिस ने बताया कि मरने वालों में PPHI का एक डिस्पेंसर, एम्बुलेंस ड्राइवर, एक सुरक्षा गार्ड और एक अन्य कर्मचारी शामिल हैं। बचाव दल के अधिकारियों से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, पीड़ितों में एक गर्भवती महिला और उसके साथ आए दो लोग शामिल थे।

स्पेन में 68 लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन? रेलवे का खराब सिस्टम या मानवीय भूल



स्पेन में दो हाईस्पीड ट्रेनों की टक्कर में 68 लोगों की मौत और 100 से अधिक घायल हुए। लाल सिग्नल के बावजूद ट्रेन आगे बढ़ने से रेल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। स्पेन में दो हाईस्पीड ट्रेनों की टक्कर में 68 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल। लाल सिग्नल के बावजूद ट्रेन आगे बढ़ने से हादसे की आशंका, जांच जारी। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के दक्षिण में बुधवार, 28 अक्टूबर की सुबह दो हाईस्पीड ट्रेनों की भीषण टक्कर में कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे में दोनों ट्रेनों के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दुर्घटना को स्पेन के इतिहास का चौथा सबसे घातक रेल हादसा बताया जा रहा है। इस साल देश में यह दूसरी बड़ी रेल दुर्घटना है। हादसे के बाद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की।

पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कम कैसे हुई? वहां हिंदू बेटियों के साथ क्या होता है

पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कम कैसे हुई? जो जनसंख्या 15 प्रतिशत थी वह अब घटकर 2 प्रतिशत से भी कम रह गई है? पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हुआ? आइए जानते हैं। ब्रिटिश संसद में पाकिस्तान में हिंदुओं के कथित उत्पीड़न पर रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में जबरन धर्म परिवर्तन, लड़कियों के अपहरण और संपत्ति पर कब्जे के आरोप। ब्रिटिश सरकार से पाकिस्तान को मिलने वाली सहायता मानवाधिकार सुधारों से जोड़ने की मांग। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की स्थिति एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चर्चा में है। ब्रिटेन स्थित प्रवासी संगठन INSIGHT UK ने ब्रिटिश संसद में एक रिपोर्ट पेश कर पाकिस्तान में हिंदुओं के कथित धार्मिक उत्पीड़न, संपत्ति पर कब्जे, जबरन धर्म परिवर्तन और महिलाओं के अपहरण जैसे गंभीर



मुद्दे उठाए हैं। रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार (British Government) से पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों में अल्पसंख्यकों (Minority) की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मांग की गई है। INSIGHT UK की यह रिपोर्ट पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता (Religious Freedom) और अल्पसंख्यकों के अधिकारों (Rights of Minorities) को लेकर कई सवाल खड़े करती है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कितनी घटी? रिपोर्ट के मुताबिक, 1941 की जनगणना में उस क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी लगभग 14.6 प्रतिशत थी, जो बाद में पश्चिमी पाकिस्तान बना। आज पाकिस्तान में हिंदुओं की हिस्सेदारी दो प्रतिशत से कम बताई जाती है। इस बदलाव के पीछे 1947 का विभाजन (Partition of India and Pakistan), बड़े पैमाने पर पलायन, समय-समय पर हुई सांप्रदायिक हिंसा (Religious Violence) और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों जैसे कई ऐतिहासिक कारण रहे हैं। रिपोर्ट का आरोप है कि हिंदू परिवारों को हिंसा और भेदभाव के कारण अपनी जमीन तथा घर छोड़ने पड़े। इसमें पुश्तैनी संपत्तियों से बेदखली की घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। क्या पाकिस्तान के कानून भी भेदभाव करते हैं? रिपोर्ट में पाकिस्तान के संविधान (Constitution of Pakistan) के अनुच्छेद 41 और 91 का हवाला दिया गया है। इन प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति (President) और प्रधानमंत्री (Prime Minister) के पद के लिए मुस्लिम होना आवश्यक है।

30 अक्टूबर यौमे-ए-वफात पर विशेष।

महान् समाज सुधारक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती

स्वामीजी का जन्म काठियावाड मे मौरवी राज्य के टंकारा नामक छोटे से ग्राम मे 12 फरवरी सन् 1824 ई. मे हुआ। आपका बचपन का नाम मूलशंकर था। पिता अंबाशंकर सनातनी ब्राह्मण थे। बालक मूलशंकर प्रारम्भ से ही प्रतिभावना तथा सजग बुध्दि के थे। शिवरात्रि के पूर्व पर एक चूहे द्वारा शिवजी की मुर्ति पर चढ जाने की घटना ने उनके जीवन को ही बदल दिया और उनका विश्वास मूर्तिपूजा व रुढियो वाले धर्म से उठ गया और वे सच्चे वैदिक धर्म की खोज मे निकल पडे। सच्चे गुरु की तलाश मे उन्होने हजारो मील की पैदल यात्रा की। अन्त मे 36 वर्ष की आयु मे उन्हे मथुरा मे 80 वर्षीय गुरु विरजानन्द जी मिल गए। विरजानन्द जी ने वेदो की शिक्षा दी । गुरु दक्षिणा के रूप में गुरूजी ने यही कहा कि " तुम मेरी दी गई विघा का प्रसार करो और अधःपतन की और जा रहे भारतीय समाज को अनेक बुराइयो से मुक्त कर सुन्दर व स्वस्थ भनाओ"।

स्वामीजी ने गुरु की आज्ञा का अक्षरशः



पालन किया और वैदिक सभ्यता व संस्कृति का धुआंधार प्रचार करने लगे। मूर्ति पूजा तथा अनेक अंध-विश्वासो की उन्होने खुलकर निन्दा की। एक ही ईश्वर निरंजन निराकर की उपासना का संदेश जन-जन तक पहुंचाया। भारत मे फैले हुए असंख्या जाति भेदो के खिलाफ उन्होने युध्द घोषणा की। विधवा विवाह के पक्ष मे जोरदार आवाज उठाकर उन्होने एक महान् सुधार की नीव रखी। स्त्री शिक्षा को समाज व राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक बताया।

इन सभी समाज सुधारो का मूल उद्देश्य भारत मे राष्ट्रीयता की आधारशिला रखकर , उस पर स्वराज का महल खडा करना था। उन्होने स्पष्ट किया कि भारतवासी केवल सुराज्य ही नही चाहते ,वरन् स्वराज्य चहाते है। स्वराज्य प्राप्त करना वैदिक संस्कृति का मूल उद्देश्य है। प्रत्येक देश के निवासियो का यह मूलभूत अधिकार है कि वे अपने देश का शासन स्वयं संचालित करे । इस तरह से स्वामीजी ने देश को सर्वप्रथम स्वराज्य का मूल मंत्र दिया। इसके अतिरिक्त अछूतोध्दार तथा पुरूष एवं स्त्रियो के समान अधिकार को राष्ट्रोन्नति के लिए आवश्यक बताया। उपर्युक्त आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए स्वामीजी ने 1875 ई. मे बम्बई मे आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की, जिसके उद्देश्य वैदिक संस्कृति का प्रचार , जाति भेदो का नाशकर कर्मानुसार वर्णाश्रम पध्दति की स्थापना , अछूतोध्दारतथा राष्ट्र मे स्वराजय की स्थापना करना आदि थे।

जिन सामाजिक व धार्मिक कुरीतियो के कारण भारतवर्ष का पतन हुआ, उनको समूल नष्ट करने मे स्वामीजी ने अपना पुरा जीवन अर्पित कर दिया। भारत मे सामाजिक व धार्मिक क्रान्ति का शंखनाद कर एक ऐसा आधार तैयार किया जिस पर आज स्वराज्य की इमारत शान से खडी है। भारतवर्ष के राष्ट्र-निर्माताओ मे स्वामीजी का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

30 अक्टूबर सन् 1883 ई.को स्वामीजी इस संसार से कूच कर गए , परन्तु समाज सुधार तथा राष्ट्रोत्थान के लिए जो उन्होने महान् कार्य किए ,उसे इतिहास गौरवशाली शब्दो मे स्मरण करेगा। आगे चलकर आर्य समाज ने लाला लाजपतराय जैसे अनेक देशभक्त प्रदान किए। जिन्होने स्वाधीनता आन्दोलन मे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया।

संदर्भ-स्वतन्त्रता संग्राम का इतिहास
लेखक-गोवर्धनलाल पुरोहित
पृष्ट संख्या 123,124
संकलन हसरत अली
शेरपुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश

MPSC परीक्षा धांधली मामले में

9 परीक्षाएं जांच आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, MPSC की 9 प्रमुख परीक्षाओं से संबंधित कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं की गहन जांच की जाएगी। औषध निरीक्षक परीक्षा गट-ब (2025) महाराष्ट्र गट-ब सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा (2025) महाराष्ट्र गट-ब सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा (2025) महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा (2025) महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा (2025) महाराष्ट्र कृषि सेवा मुख्य परीक्षा (2024) अन्न एवं औषध प्रशासन सेवा मुख्य परीक्षा (2023) महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (2025) महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (2025) निवेदन एवं साक्ष्य जमा करने के लिए दिशानिर्देश सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, शिकायतकर्ताओं और गवाहों के लिए कई व्यवस्थाएं की गई है। भाषा का विकल्पः अभ्यर्थी और संबंधित व्यक्ति अपने निवेदन मराठी या अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजः निवेदन के साथ एक वैध पहचान पत्र की प्रति और साक्ष्य दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड प्रतियां प्रतिज्ञापत्र के साथ जोड़ना अनिवार्य है। कार्यालय का पताः लिखित निवेदन और कागजात मुंबई स्थित आयोग के कार्यालय अन्न व औषध प्रशासन भवन, दालन क्रमांक 201, दूसरी मंजिल, बीकेसी, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 में जमा कराए जा सकते हैं। ई-मेल सुविधाः ऑनलाइन माध्यम से दस्तावेज भेजने के लिए आयोग की आधिकारिक ई-मेल आईडी complaints.inquirycomm.mpsc@maharashtra.gov.in उपलब्ध कराई गई है।

25 वर्षे विकासाची 25 मिरा भाईंदर महानगरपालिका "माझे शहर, माझा अभिमान"

मिरा भाईंदर महानगरपालिका
मुख्यालय, २रा मजला, स्व. इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.)
दूरध्वनी क्र.०२२-२८१९२८२८ ई-मेल आयडी pwd@mbmc.gov.in
// बांधकाम / विद्युत विभाग //

पुण्यश्लोक 300

जा.क्र. मनपा/साबां/वि./५०/२०२६-२७ दि.२९/१०/२०२६

// फेर निविदा सुचना क्र. ५०//

कामाचे नाव :- मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे गोडदेव गोल्डन नेस्ट येथे नागरी सुविधा क्षेत्र मधील जागेत महिला भवन बांधणे.

अंदाजपत्रकीय रक्कम (रु.) रु. २३,६६,०८,१३२/-

निविदा पुस्तिका ई - टेंडरींग (E — Tendering) संगणक प्रणालीच्या https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर दि.०२/११/२०२६ ते दि.११/११/२०२६ रोजी उपलब्ध होतील.

सदर निविदाबाबतची निविदापुर्व बैठक (Prebid meeting) दि.०९/११/२०२६ रोजी दुपारी १२.०० वाजता शहर अभियंता यांच्या दालनात आयोजित करण्यात येणार आहे.

तसेच दि.१२/११/२०२६ रोजी १२.०० वाजेपर्यंत निविदा स्विकारण्यात येतील व दि.१३/११/२०२६ रोजी १२.३० वाजता उघडण्यात येतील.

कोणतीही निविदा स्विकारणे अथवा नाकारण्याचा अधिकार मा. आयुक्त, मिरा भाईंदर महानगरपालिका यांनी राखून ठेवला आहे.

DEEPAK BHASKAR KHAMBIT Digitally signed by DEEPAK BHASKAR KHAMBIT Date: 2026.10.29 14:27:11 +05'30'

शहर अभियंता
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

जा. क्र. मनपा/मावाज/ E-१००८५०८३ /२०२६-२७
दि. २९/१०/२०२६

पृष्ठ 1/8 का शेष

भिवंडी में 100 मीटर के दायरे

रिपोर्ट के मुताबिक, निरीक्षण के दौरान संजय नगर का स्वास्थ्य केंद्र बंद मिला। यहां कामकाज का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक निर्धारित बताया गया है। हालांकि, एक कर्मचारी के अनुसार, मरीजों की जांच दोपहर 2 बजे तक ही की जाती है। न्यू आजाद नगर का केंद्र भी बंद पाया गया। वहीं, बिलाल नगर केंद्र में हर महीने आने वाले मरीजों की संख्या एक हजार से कम बताई गई है। अन्य केंद्रों पर प्रतिदिन 20 से 45 मरीज आने की जानकारी सामने आई है। इन आंकड़ों की पुष्टि और केंद्रों की वास्तविक उपयोगिता का आकलन करने की मांग की गई है। स्थायी समिति ने स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं के स्टॉक, मरीजों के रिकॉर्ड, दवा वितरण और कर्मचारियों की उपस्थिति से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। दवाओं की खरीद और वितरण में कथित अनियमितताओं की आशंकाओं को देखते हुए मामले की जांच की मांग भी की गई है। महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग की प्रतिनिधि डॉ. बुशरा सैयद की ओर से व्यवस्था में गलती स्वीकार किए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, केंद्रों को इतने कम अंतर पर स्थापित करने के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिल सका। अब विभाग से अगली बैठक में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने की अपेक्षा की गई है। एक ओर शांतिनगर में स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति और उनके स्थान चयन पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के अन्य इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी सामने आई है। नगरसेविका हुजैफा हलीम अंसारी ने किदवई नगर टाकिया क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की मांग की है। अब निगाहें महानगरपालिका की अगली रिपोर्ट पर हैं। समिति यह जानना चाहती है कि तीनों केंद्रों की स्थापना के पीछे क्या आधार था, बंद केंद्रों की स्थिति क्या है और सरकारी खर्च के अनुरूप नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का कितना लाभ मिल रहा है।

भिवंडी मनपा में बवाल: महापौर

इस घटनाक्रम ने महानगरपालिका में महिला नगरसेविकाओं के कामकाज में उनके पतियों के कथित हस्तक्षेप का मुद्दा फिर चर्चा में ला दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों और अधिकारों के बीच उनके परिजनों की भूमिका कहां तक उचित है। हालांकि, इस मामले में संबंधित पक्ष का विस्तृत पक्ष सामने आना बाकी है। महापौर के कक्ष तक पहुंचकर कुर्सी खींचने की घटना के बाद मनपा मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। चर्चा है कि सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद ऐसा घटनाक्रम कैसे हुआ। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और महापौर की ओर से की गई केस दर्ज करने की मांग पर क्या कार्रवाई होती है।

महाराष्ट्र FDA की राज्यव्यापी

जांच के दौरान मिठाई, दुग्ध उत्पाद, चावल, सूखे मेवे और अन्य खाद्य पदार्थों की पड़ताल की गई। लेबल पर जरूरी जानकारी की कमी, गुणवत्ता मानकों के संभावित उल्लंघन और अस्वच्छ भंडारण की आशंका के आधार पर कार्रवाई की गई। मुंबई की चार दुकानों से खाद्य सामग्री जब्त मुंबई शहर में यशोदा डेयरी से 76,510 रुपये मूल्य का 250.50 किलो खाद्य पदार्थ जब्त किया गया। इसमें दूध पाउडर, भैंस का दूध और पनीर शामिल हैं। क्लासिक एंटरप्राइजेज से 35,520 रुपये मूल्य का 296 किलो टूटा चावल बरामद किया गया। इसके अलावा गीतांजलि कैटरिंग सर्विसेज से 36 हजार रुपये मूल्य का 72 किलो मोहनथाल और अरिहंत स्वीट्स से 1 लाख 22 हजार 260 रुपये मूल्य की 240.50 किलो विभिन्न मिठाइयां जब्त की गईं। अरिहंत स्वीट्स की मिठाइयों में अतिरिक्त रंग मिलाए जाने का संदेह जताया गया है।

शिवसेना (UBT) सांसद संजय

न्यायपालिका से जुड़े सार्वजनिक बयान देते समय वह उचित संयम और सावधानी बरतेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीशों के आचरण से संबंधित कोई तथ्यात्मक टिप्पणी करने से पहले उसकी पूरी तरह पुष्टि करेंगे। 17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे राउत सुनवाई के दौरान माफीनामा अदालत के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, राउत की ओर से कोई वकील भी पेश नहीं हुआ। इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया। अब अदालत उस दिन राउत के माफीनामे पर विचार करेगी और मामले में आगे का निर्णय लेगी। फिलहाल, माफी दाखिल किए जाने के बावजूद अवमानना से जुड़े मामले में अंतिम फैसला आना बाकी है।

शिवसेना विवादः सुप्रीम कोर्ट

मनिंदर सिंह ने शिवसेना संगठन के अंदर होने वाले आंतरिक चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब पार्टी के अंदर होने वाले चुनाव सही ढंग से नहीं कराए गए तो ऐसे में इस आधार पर पार्टी के नेतृत्व का फैसला नहीं लिया जा सकता है। सिंह ने कहा कि 2018 में शिवसेना के संविधान में बदलाव के बाद पार्टी के अंदर बिना चुनाव के अपॉइंटमेंट किए गए। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में किसके पास बहुमत है, यह विधायकों की संख्या के आधार पर तय होता है। ऐसे में शिवसेना विवाद मामले में विधायकों के बहुमत को नकारा नहीं जा सकता है। उद्धव खुद फैक्ट्स भूल जाते हैं। शिंदे गुट के वकील सिंह ने अपनी दलील के दौरान सुभाष देसाई केस का भी जिक्र किया। उन्होंने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि वह खुद भूल जाते हैं कि किसी भी पार्टी के चुने चुने हुए विधायक व सांसदों को मिले वोटों के प्रतिशत के आधार पर सिंबल मिलता है। साथ ही पार्टी में किसके पास मेजॉरिटी है, यह तय करने के लिए विधायकों व सांसदों का नंबर जरूरी हैं। इस मामले में उद्धव गुट के मुकाबले एकनाथ शिंदे गुट को ज्यादा विधायकों व सांसदों का समर्थन है। इस लिहाज से शिवसेना का नेतृत्व शिंदे के पास ही होना चाहिए। EC के पास पार्टी की मान्यता रद्द करने का अधिकार शिंदे गुट के वकील सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के पास किसी भी पार्टी की मान्यता को रद्द करने का अधिकार है। अगर कोई पार्टी अंदरूनी चुनाव नहीं कराती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसिल हो जाता है। पार्टी के ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर का टेस्ट पूरी तरह से चुनावों पर निर्भर करता है। यह दलील देना कि चुनाव आयोग के पास मान्यता रद्द करने का अधिकार नहीं है, सही नहीं है। उन्होंने यह सवाल उठाया कि अगर हम नॉमिनेशन का तरीका इस्तेमाल करते है, तो क्या हम इसके माध्यम से पार्टी चीफ को चुनेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर एक ट्रिब्यूनल है शिंदे गुट की ओर से उनके वकील ध्रुव मेहता ने दलील देते हुए कहा कि 21 जून 2022 को हुई मीटिंग के समय एकनाथ शिंदे शिवसेना विधायक दल के नेता थे। उनके साथ हुई हुई मीटिंग में विधायकों ने भरत गोगावले को व्हिप चुना। ऐसे में गोगावले की नियुक्ति पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। मेहता ने कहा कि इस केस की ओरिजिनल पिटीशन में लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं।

भिवंडी में प्रदूषण पर शिकंजा, 60 औद्योगिक इकाइयां बंद; 79 पर कार्रवाई अटकी

डाइंग, टेक्सटाइल और साइजिंग इकाइयां रडार पर, 192 निर्माण परियोजनाओं को नोटिस; 32 बेकरी को गैस या इलेक्ट्रिक ओवन अपनाने का निर्देश

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान

भिवंडी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए महानगरपालिका और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (एमपीसीबी) ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्रदूषण फैलाने वाली डाइंग, टेक्सटाइल और साइजिंग इकाइयों पर शिकंजा कसते हुए अब तक 60 इकाइयां बंद की जा चुकी हैं। हालांकि, 79 इकाइयों के मामले अब भी लंबित हैं। ऐसे में शहर की हवा को साफ करने की मुहिम के बीच कार्रवाई की रफ्तार और उसके नतीजों पर सवाल उठ रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, भिवंडी की 249 औद्योगिक इकाइयों में से 110 का डेटा उपलब्ध है, जबकि 60 इकाइयों को बंद किया गया है और 79 के मामले लंबित हैं। इनमें 54 डाइंग, 74 टेक्सटाइल और 121 साइजिंग इकाइयां शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, 54 डाइंग इकाइयों में से 12 बंद की गई हैं, 33 का डेटा उपलब्ध है और नौ के मामले लंबित हैं। वहीं, 74 टेक्सटाइल इकाइयों में से 17 बंद की गई हैं, 37 का डेटा उपलब्ध है और 20 के मामले लंबित हैं। साइजिंग इकाइयों की स्थिति और भी चिंताजनक है। कुल 121 इकाइयों में से 31 बंद की गई हैं, 40 का डेटा उपलब्ध है, जबकि 50 इकाइयों के मामले लंबित हैं। एमपीसीबी ने 22 साइजिंग, सात डाइंग और 29



टेक्सटाइल इकाइयों को बंद करने के नोटिस

जारी किए हैं। औद्योगिक इकाइयों के अलावा निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल भी शहर के वायु प्रदूषण की बड़ी वजह है। इसे देखते हुए महानगरपालिका के नगर नियोजन विभाग और पांच प्रभाग समितियों ने 192 निर्माण परियोजनाओं को नोटिस जारी किए हैं। निर्माण स्थलों पर धूल रोकने के उपाय करने, मलबे का उचित निस्तारण करने और सड़क पर निर्माण सामग्री नहीं फैलाने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाली परियोजनाओं के खिलाफ आगे कितनी सख्ती दिखाई जाती है। लकड़ी के इस्तेमाल से होने वाले धुएं पर नियंत्रण के लिए शहर की 32 बेकरी को एक महीने के भीतर पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) या इलेक्ट्रिक ओवन अपनाने का निर्देश दिया गया था। निर्धारित समयसीमा बीतने के बाद भी नियमों का पालन नहीं करने वाली बेकरी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए महानगरपालिका प्रमुख सड़कों पर सफाई मशीनों के इस्तेमाल और पानी के छिड़काव की व्यवस्था करने की तैयारी में है। इसके अलावा सड़कों और फ्लाईओवर की सफाई के लिए उच्च दबाव वाली पानी की मशीनों का उपयोग करने की योजना है। फॉगिंग मशीनों के इस्तेमाल की भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि धूल के कणों को हवा में फैलने से रोका जा सके। भिवंडी में औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण कार्यों और ईंधन से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण पर नियंत्रण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इकाइयों को नोटिस जारी करना और बंदी की कार्रवाई करना अहम कदम हैं, लेकिन इसका वास्तविक असर तभी दिखेगा, जब नियमों का लगातार पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अब सवाल यह है कि लंबित मामलों का निपटारा कब होगा और प्रदूषण कम करने के लिए उठाए जा रहे कदम जमीन पर कितने प्रभावी साबित होंगे।

मुंबई में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर RTO की कार्रवाई, 5,821 गाड़ियों पर 6.20 करोड़ रुपये का जुर्माना



15 अक्टूबर तक 31,899 वाहनों की जांच में 5,821 नियम तोड़ते मिले। परिवहन विभाग ने 6.20 करोड़ जुर्माना लगाया, करीब 31% वसूला। हाई कोर्ट की चिंता के बाद आरटीओ ने प्रदूषण नियंत्रण जांच तेज की। मुंबई महानगर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग ने वाहनों के खिलाफ जांच अभियान तेज कर दिया है। 1 से 15 अक्टूबर के बीच 11 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) ने कुल 31,899 वाहनों की जांच की। इनमें 5,821 वाहन नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। इन पर कुल 6 करोड़ 20 लाख 90 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि अब तक 1 करोड़ 92 लाख 17 हजार 490 रुपये की वसूली हुई है। आंकड़ों के अनुसार, कुल जुर्माने की करीब 31 प्रतिशत राशि ही वसूल हो पाई है।

भिवंडी में 100 मीटर के दायरे में 3 स्वास्थ्य केंद्र, दो बंद मिलने पर उठे सवाल

हर केंद्र पर 21.50 लाख रुपये खर्च होने की जानकारी, फ्लाईओवर के नीचे पड़ा पोर्टेबल केबिन भी महीनों से बेकार

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान

भिवंडी के शांतिनगर इलाके में महानगरपालिका की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी खर्च को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां महज 100 मीटर के दायरे में तीन शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (UHWC) स्थापित किए गए हैं। इनमें से दो केंद्र निरीक्षण के दौरान बंद मिले, जबकि एक पोर्टेबल स्वास्थ्य केबिन राजीव गांधी फ्लाईओवर के नीचे महीनों से बेकार पड़ा होने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में केंद्रों के स्थान चयन, उपयोगिता और खर्च को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार, भिवंडी-निजामपुर



शहर महानगरपालिका ने मुंबई पाइपलाइन के किनारे बिलाल नगर, संजय नगर और न्यू आजाद नगर में ये स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। शुक्रवार को हुई स्थायी समिति की बैठक में इन केंद्रों की जरूरत, उनके बीच की दूरी और खर्च का मुद्दा उठाया गया। बताया गया कि प्रत्येक केंद्र पर करीब 21.50 लाख रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि कुल खर्च लगभग 68.50 लाख रुपये बताया गया है। स्वास्थ्य केंद्रों के स्थान चयन को लेकर जनसंख्या संबंधी मानकों के पालन पर भी सवाल उठाए गए। बताया गया कि सामान्य मानकों के अनुसार, 10 हजार से 15 हजार की आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। ऐसे में महज 100 मीटर के दायरे में तीन केंद्र स्थापित करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर समिति ने जानकारी मांगी है। केंद्रों के चयन से जुड़े दस्तावेजों और जनसंख्या सर्वेक्षण की जांच की मांग भी की गई है। ...शेष 7 पर

महाराष्ट्र FDA की राज्यव्यापी कार्रवाई: 24.92 लाख मूल्य का 6,495 किलो मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त



FDA ने 6,495 किलो खाद्य सामग्री जब्त की। मुंबई की चार दुकानों पर कार्रवाई हुई। नागपुर में 1,795 किलो सोनपापड़ी जब्त की गई। Maharashtra FDA Statewide Food Raid: मुंबई में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने महाराष्ट्र में विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान मुंबई की चार दुकानों सहित राज्य के विभिन्न विभागों में कुल 6,495 किलो खाद्य सामग्री जब्त की गई। जब्त सामग्री की कीमत 24 लाख 92 हजार 455 रुपये बताई गई है। ...शेष 7 पर

भिवंडी मनपा में बवाल: महापौर की कुर्सी खींचकर बैठ नगरसेविका का पति, केस दर्ज करने की मांग

सड़कों की बदहाली के विरोध में किया प्रदर्शन, घटना का वीडियो वायरल; महापौर कक्ष की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान

भिवंडी महानगरपालिका में सोमवार को उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब एक नगरसेविका के पति ने महापौर की गैरमौजूदगी में उनके कक्ष में पहुंचकर कथित तौर पर उनकी कुर्सी खींच ली और उस पर बैठकर अपने वार्ड की बदहाल सड़कों का मुद्दा उठाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मनपा मुख्यालय में हलचल मच गई। महापौर नारायण चौधरी ने इस मामले में संबंधित व्यक्ति



के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार, नगरसेविका नगमा सिद्दीकी के पति सुल्तान सिद्दीकी सोमवार को महापौर के कक्ष में पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों की अनदेखी करते हुए महापौर की कुर्सी खींची और उसके सामने बैठकर अपने वार्ड की खराब सड़कों तथा नागरिकों की समस्याओं को लेकर विरोध जताया। घटना के समय महापौर कक्ष में मौजूद नहीं थे। घटना का वीडियो सामने आने के बाद महापौर नारायण चौधरी ने नाराजगी जताई और प्रशासन से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि शहर के विकास कार्यों के लिए वे प्रतिबद्ध हैं और किसी के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेंगे। ...शेष 7 पर

यह दैनिक मालक-मुद्रक-प्रकाशक, संपादक मोहम्मद शकील अब्दुल रफीक ने सिटी इन्टरप्राजेस धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे से प्रकाशित किया, मुख्य कार्या लय- धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे महाराष्ट्र।मुंबई कार्या लय- शॉप नं. 14 उपाध्याय इंडस्ट्रियल इस्टेट, दहिसर चेक नाका, मुंबई इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधीन होगा संपादक मो. शकील अ. रफीक : मो. 9869128483
Email : shakeelsahara@gmail.com / citynewsmumbai@gmail.com website : www.citynewsmumbai.in RNI No. : MAHHIN/2012/47486